

प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री का पद भार संभालते ही आज किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किश्त जारी की है। ये किश्त नौ करोड़ 30 लाख किसानों को लगभग बीस हजार करोड़ रुपये का लाभ पहुंचाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का पहला निर्णय, किसानों के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में उनकी सरकार, कृषि क्षेत्र और किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य करेगी।

मनीष गर्ग

भारतीय निर्वाचन आयोग ने सात राज्यों में 13 विधानसभा क्षेत्रों के रिक्त स्थानों के लिए उप-चुनावों की अनुसूची जारी कर दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने आज शिमला में बताया कि बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडू, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के तीन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव आयोजित होंगे। उन्होंने बताया कि कांगड़ा जिला के देहरा, हमीरपुर जिला के हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र और सोलन जिला के नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 10 जुलाई को उप-चुनाव के लिए मतदान होगा जबकि 13 जुलाई को मतगणना होगी। मनीष गर्ग ने बताया कि प्रदेश में उप-चुनावों के लिए राजपत्रित अनुसूची 14 जून, को जारी की जाएगी और नामांकन पत्र भरने की अन्तिम तिथि 21 जून तय की गई है जबकि 24 जून को नामांकन पत्रों की छंटनी होगी और 26 जून नामांकन वापिस लेने की अन्तिम तिथि होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 15 जुलाई से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि संबंधित जिलों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य के लोगों को परिवहन सुविधाएं प्रदान करने में हिमाचल पथ परिवहन निगम की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिमला में आज निगम की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए 25 नई वॉल्वो बसें और 50 टेंपो ट्रैल्वर खरीदे जाएंगे। इसके अलावा निगम के बेड़े में इलैक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी जिनके प्रापण के लिए प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष में इलैक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 5 सौ 17 करोड़ रूपए का बजट आबंटित किया गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में सीमित हवाई रेल नेटवर्क के दृष्टिगत लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए निगम के संचालन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निगम को प्रतिमाह 63 करोड़ रूपए प्रदान करेगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में परिवहन सुविधा को सुदृढ़ करने के साथ ही पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में इलैक्ट्रिक बसों की विशेष भूमिका रहेगी।

सुक्खू

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार दिल्ली सरकार के साथ किए गए समझौते के अनुसार दिल्ली को पानी देने के लिए प्रतिबद्ध है। शिमला में आज पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात कही। प्रदेश के तीन विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उप चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन तीनों निर्दलीय विधायकों ने निजी लाभ के लिए अपनी सदस्यता को दांव पर लगाया है। उन्होंने कहा कि लोगों ने उन्हें पांच साल के लिए अपने क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए चुना था लेकिन निजी स्वार्थ के चलते निर्दलीय विधायकों ने राज्य पर उप चुनाव का बोझ डाला है।

जगत सिंह नेगी

जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों में पात्र लोगों को नौतोड़ भूमि प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। शिमला से जारी एक ब्यान में उन्होंने कहा कि राज्य में हिमाचल प्रदेश नौतोड़ भूमि नियम 1968 के तहत 20 बीघा से कम भूमि वाले पात्र लाभार्थियों को 20 बीघा सरकारी भूमि प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। इसके तहत जनजातीय लोगों को लाभान्वित किया गया है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के फलस्वरूप प्रदेश में प्रार्थियों को नौतोड़ भूमि आबंटित नहीं की जा सकी। उन्होंने कहा कि नौतोड़ के कई मामले अभी भी लंबित पड़े हैं। जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों से राज्यपाल से वन संरक्षण अधिनियम 1980 को हटाने का आग्रह किया है ताकि पात्र लाभार्थियों को नौतोड़ भूमि प्रदान की जा सके।
